(d) if so, the reasons therefor, and if not, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND PROGRAMME IMPLEMENTATION AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI SUKH RAM): (a) The State Government has reported an expenditure of 102.72 percent in 1989-90 and 90.65 per cent in 1990-91. The expenditure upto September, 1992 is not available.

(b) Plans are prepared on the basis of resources and having regard to the needs of development.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise

ग्रामीण व्यक्ति की औसत आय

2779. **श्री राम सिंह राठवा**: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष ग्रामीण व्यक्ति की औसत आय कितनी थी;

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान उसकी औसत आय में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ग) ग्रामीणों की आमदनी में वृद्धि करने के उद्देश्य से सरकार के विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) और (ख) 1970-71 तथा 1980-81 वर्षों के लिए प्रति व्यक्ति ग्रामीण आय का अनुमान केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी एस ओ) में तैयार किया गया है तथा जुलाई 1989 की मन्थली एब्सट्रैक्ट आफ स्टेटिसटिक्स में प्रकाशित किया गया। वर्तमान कीमतों पर ग्रामीण भारत में प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद 1970-71 तथा 1980-81 में क्रमशः 499.4 तथा 1242 रुपए था। पिछले वर्ष के लिए देश के एक ग्रामीण की औसत आय तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान उसकी वृद्धि के अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रकों के विकास के लिए तथा ग्रामीण लोगों की आय बढ़ाने के लिए भी विकास स्कीमों तथा कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। उत्पादकता तथा कृषि में वृद्धि करने तथा आय बढ़ाने की दृष्टि से फसल उत्पादन, मुद्रा संरक्षण, बागवानी, पशु पालन, मछली पालन, रोपड़ फसलें, अनुसंधान सहकारिता तथा ऋण के लिए विशेष स्कीमों को क्रियान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण गरीबों की आय बढ़ाने तथा रोजगार अवसर सृजित करने के लिए कई कार्यक्रमों को भी क्रियान्वित किया जा रहा है जिसमें एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडी पी) तथा जवाहर रोजगार योजना (जेआरवाई) शामिल हैं। इसके अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना (एससीपी) तथा जनजाति उपयोजना (टीएसपी) कार्यान्वित की जा रही है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने हेतु उत्तर प्रदेश की परियोजनाएं

2780. **श्री ईश दत्त यादव**: क्या योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने हेतु परियोजनाओं/योजनाओं की कोई सूची भेजी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) किन-किन परियोजनाओं/योजनाओं को विश्व बैंक की सहायता से अलग से कार्यान्वित किया जाएगा?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्त्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिए कई परियोजनाओं/स्कीमों से युक्त प्रारूप आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-97 तथा वार्षिक योजना 1992-93 प्रस्तुत किया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए 21000 करोड़ रुपए के परिव्यय का अनुमोदन किया गया है।

(ख) उपरिलिखित दस्तावेज में स्कीम/परियोजनावार ब्यौरे दिये गये हैं जो पहले ही संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ग) दस्तावेज के खण्ड 3 में विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त परियोजनाओं सहित विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में क्रियान्वयन के लिए विश्व बैंक के विचारार्थ मौजूदा परियोजनाएं हैं:—

	परियोजना का नाम	राशि (मिलियन डालर में)
1.	यू पी सोडिक परियोजना	100
2.	प्रथम प्राथमिक शिक्षा परियोजना	150

रोजगार हेतु निर्धारित लक्ष्य

2781. **श्री राम सिंह राठवा**: क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रोजगार उपलब्ध कराने के लिए निर्धारित किया गया लक्ष्य क्या था;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है; और

(ग) सरकार को किन-किन कारणों से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पायी है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) से (ग) रोजगार मुहैय्या कराने के लक्ष्य साल दर साल आधार पर निर्धारित नहीं किए जाते हैं। जनवरी, 1988 (राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित पिछले व्यापक सर्वेक्षण का मध्य बिन्दु) तथा मार्च, 1992 के अन्त में सामान्य रूप से रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की संख्या में लगभग 232 लाख अर्थात् प्रतिवर्ष औसतन 55 लाख की बढ़ोतरी का अनुमान है।

राज्यों द्वारा आठवीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप दिया जाना

2782. **श्री शंकर दयाल सिंह**: क्या **योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सभी राज्यों ने आठवीं पंचवर्षीय योजना और अपनी-अपनी वार्षिक योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इसमें संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार का क्या योगदान रहा है?

योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री और गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम): (क) से (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना तथा वार्षिक योजना 1992-93 के लिए संबंधित राज्य सरकारों तथा केन्द्र सरकार के अंशदान संबंधी राज्यवार ब्यौरों को दर्शाता हुआ एक विवरण संलग्न है। **(नीचे देखिए)** वार्षिक योजना 1993-94 के लिए सभी राज्यों के परिव्ययों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

विवरण

आठवीं योजना के लिए कुल परिव्यय राज्यों के निजी स्रोतों तथा केन्द्रीय सहायता

(करोड़ रु०)

राज्य	सहमति कुल परिव्यय	राज्यों के निजी स्रोत	केन्द्रीय सहायता
1	2	3	4
1. **विशेष श्रेणी**			
1. अरुणाचल प्रदेश	1155.00	0.00	1155.00
2. असम	4662.00	0.00	4662.00
3. हिमाचल प्रदेश	2502.00	449.86	2052.14
4. जम्मू और कश्मीर	4000.00	0.00	4000.00
5. मणिपुर	979.00	0.00	979.00
6. मेघालय	1029.00	0.00	1029.00
7. मिजोरम	763.00	0.00	763.00
8. नागालैंड	844.00	0.00	844.00
9. सिक्किम	550.00	6.70	543.30
10. त्रिपुरा	1130.00	44.91	1085.09